eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

भारतीय वित्तीय समावेशन नीतियों का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव (2010–2021)

डा0 मनोज कुमार अवस्थी[1]
[1]सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, का0न0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही, उ0प्र0

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

वित्तीय समावेशन किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 2010 से 2021 के बीच अनेक नीतिगत पहलों जैसे जन धन योजना, डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सूक्ष्म वित्त सेवाएँ एवं छोटे उद्यमों को ऋण सहायता कृ के माध्यम से वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया। इस शोधपत्र में इन पहलों का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं में कमी, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, और समग्र आर्थिक विकास पर इनके प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इस अवधि में उत्पन्न चुनौतियों, सफलताओं और आगामी सुधार के संभावित क्षेत्रों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। यह अध्ययन नीतिगत विश्लेषण, सरकारी रिपोर्टों, वैश्विक सूचकांकों और प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है।

मुख्य शब्द– वित्तीय समावेशन, जन धन योजना, डिजिटल भुगतान, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, भारत, वित्तीय साक्षरता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन।

Introduction

वित्तीय समावेशन 21वीं सदी के आर्थिक विकास मॉडल का एक केंद्रीय तत्व बन चुका है। विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, जहां आर्थिक विषमताएँ गहरी हैं, वित्तीय समावेशन केवल बैंकों के माध्यम से सेवाओं तक पहुँच नहीं है, बल्कि यह एक सशक्तिकरण प्रक्रिया है जो समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत जैसे विविध और विशाल आबादी वाले देश में, वित्तीय समावेशन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 2010 के बाद भारत ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए अनेक प्रभावशाली नीतियाँ और कार्यक्रम आरंभ किए। इसमें बैंकों के भौतिक विस्तार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना शामिल है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) ने करोड़ों वंचित भारतीयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी।

वित्तीय समावेशन का सामाजिक प्रभाव भी गहरा रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच ने गरीबों को औपचारिक ऋण व्यवस्था, बीमा सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने में मदद की, जिससे उनकी आजीविका में स्थायित्व आया। हालाँकि, इस यात्रा में अनेक चुनौतियाँ भी उभर कर आईं जैसे वित्तीय साक्षरता की कमी, डिजिटल डिवाइड, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच की सीमाएँ, तथा संस्थागत क्षमता की कमी। महामारी (COVID–19) के दौरान वित्तीय समावेशन की उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आई जब सरकार ने DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि पहुँचाई।

यह शोधपत्र 2010 से 2021 के बीच भारत सरकार द्वारा लागू की गई वित्तीय समावेशन नीतियों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इन नीतियों के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और उद्यमिता के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नों पर केन्द्रित है:

वित्तीय समावेशन नीतियों ने भारतीय समाज में किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न की?
किन वर्गों को सर्वाधिक लाभ हुआ और कौन–से वर्ग अब भी वंचित हैं?
इन नीतियों के कार्यान्वयन में कौन–सी बाधाएँ सामने आईं?
भविष्य में वित्तीय समावेशन को और अधिक समावेशी और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
यह शोध सैद्धांतिक समीक्षा, सरकारी रिपोर्टों, विश्व बैंक तथा RBI जैसी संस्थाओं के डाटा, और विभिन्न सर्वेक्षणों के विश्लेषण पर आधारित है।

अतः यह अध्ययन न केवल पिछली नीतियों का मूल्यांकन करेगा, बल्कि वित्तीय समावेशन को व्यापक और टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य की राह भी सुझाएगा।

.वित्तीय समावेशन की अवधारणा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य– वित्तीय समावेशन का अर्थ है उन सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को किफायती लागत पर उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की सुलभता प्रदान करना, जो उनकी आवश्यकताओं लेन–देन, बचत, ऋण, बीमा, और पेंशन कृ को पूरा कर सकें। सरल शब्दों में, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। बैंक खाता खोलने की सुलभता, क्रेडिट सेवाओं तक पहुँच, बचत और निवेश विकल्पों की उपलब्धता, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, डिजिटल भुगतान साधनों की पहुँच, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वित्तीय समावेशन के प्रमुख घटक हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी सेवाएँ सस्ती, सुलभ, सुरक्षित और ग्राहकों के अनुकूल हों।

आर्थिक विकास अर्थात जब वंचित समूहों को औपचारिक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, तो वे बचत और निवेश के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। गरीबी उन्मूलन अर्थात वित्तीय साधनों तक पहुँच से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या घटाई जा सकती है। सामाजिक समानता यानी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक अंतर को कम किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक दर्जा बढ़ता है। रोजगार सृजन यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता मिलने से नए रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं। संकट प्रबंधन यानी स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी के समय बीमा और बचत योजनाएँ सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन का महत्व बहुआयामी प्रतीत होता है।

विश्व स्तर पर, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

G20 Financial Inclusion Action Plan (2010) पहल वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए वैश्विक नीति ढांचा प्रदान करती है।

Alliance for Financial Inclusion (AFI) वैश्विक नेटवर्क 90 से अधिक देशों के नियामकों को वित्तीय समावेशन नीतियों के विकास में सहायता करता है।

UN's Sustainable Development Goals (SDGs) वित्तीय समावेशन को गरीबी उन्मूलन (SDG 1) और लैंगिक समानता (SDG 5) जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन माना गया है।

World Bank*s Universal Financial Access 2020 (UFA2020) इसका उद्देश्य 2020 तक सभी वयस्कों के लिए एक ट्रांजेक्शन अकाउंट सुनिश्चित करना था।

वैश्विक स्थिति–

विश्व बैंक के Global Findex Database (2017) के अनुसार–
विश्व स्तर पर लगभग 69% वयस्कों के पास कोई न कोई वित्तीय खाता था।
2011 से 2017 के बीच 1.2 अरब से अधिक वयस्कों ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव किया।
विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु लैंगिक असमानता बनी रही।

वित्तीय समावेशन में बाधाएँ– कम आय और आर्थिक अस्थिरता, भौगोलिक कठिनाइयाँ (दूरदराज के क्षेत्र), डिजिटल डिवाइड और तकनीकी साक्षरता की कमी, कानूनी और नियामकीय सीमाएँ, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएँ वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को प्रभावित करने वाली मुख्य बाधाएँ है।

भारत ने वैश्विक वित्तीय समावेशन प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका निभाई है।
Global Findex (2017) के अनुसार, भारत में 2014–2017 के बीच 30 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाता खोला।
2011 में भारत में केवल 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था, जो 2017 तक बढ़कर 80% हो गया।
डिजिटल भुगतान साधनों (जैसे भीम ऐप, यूपीआई) के कारण वित्तीय लेन–देन की पहुँच में असाधारण वृद्धि हुई है।

भारत में वित्तीय समावेशन की नीतियाँ (2010–2021)– भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा नई नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 में वित्तीय समावेशन को एक औपचारिक नीति लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। 2010 के बाद से, भारत सरकार और RBI ने मिलकर इसे एक व्यापक अभियान का रूप दिया। 2010–2021 की अवधि के दौरान कई ऐसी नीतियाँ और योजनाएँ सामने आईं, जिनका उद्देश्य था वंचित और पिछड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ना और उन्हें आर्थिक प्रवाह में सहभागी बनाना।

नीति निर्माण में दो स्पष्ट रुझान देखे जा सकते हैं–

बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का विस्तार

डिजिटल तकनीकों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना

प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014– हर घर में कम से कम एक बैंक खाता, शून्य बैलेंस खाता खोलने की सुविधा, रूपे डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा के साथ, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 के मुख्य लक्ष्य हैं। अगस्त 2021 तक 43 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। 1.5 लाख से अधिक बैंक मित्रों (Bank Mitras) के माध्यम से गाँव–गाँव सेवा पहुँचाई गई। 28,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल बैलेंस प्रमुख उपलब्धियाँ

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

हैं। गरीब परिवारों की सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे खातों में पहुँचने लगे। नकद रहित लेन–देन को बढ़ावा मिला यह सामाजिक प्रभाव दिखाई दिए। सरकारी सब्सिडी और योजनाओं के लाभार्थियों तक बिना बिचौलियों के सीधे धनराशि स्थानांतरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) का लक्ष्य प्राप्त हुआ। गैस सब्सिडी (PAHAL योजना), वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और मनरेगा मजदूरी का भुगतान मुख्य पहल है। भ्रष्टाचार में कमी, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 प्रभाव है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने निश्चित ही भारत के वित्तीय समावेशन परिदृश्य को बदल दिया। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 2014 से 2017 के बीच नए खुले खातों का 55% हिस्सा जन धन योजना के तहत था। यह भारत की सबसे सफल वित्तीय समावेशन पहलों में से एक साबित हुई। योजना की सफलता ने यह प्रमाणित किया कि एक संगठित, लक्ष्य आधारित, और टेक्नोलॉजी समर्थित अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाए जा सकते हैं।

मुद्रा योजना (Micro Units Development and Refinance Agency & MUDRA (2015) - सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी ऋण प्रदान करना, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना योजना के लक्ष्य है, शिशु (Shishu) ₹50,000 तक, किशोर (Kishore)रू ₹50,001 से ₹5 लाख तक, तरुण (Tarun) ₹ 5 लाख से ₹10 लाख तक से सहायता से लाखों छोटे उद्यमों को व्यवसाय विस्तार के लिए वित्तीय सहायता मिली, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना ने भारत में नवउद्यमिता की एक नई लहर उत्पन्न की। इन दोनों पहलों ने विशेष रूप से उन वर्गों को केंद्र में रखा जिन्हें पहले पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं से वंचित रखा गया था। भारत के वित्तीय समावेशन अभियान में इन योजनाओं ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2015–2021 की अवधि में मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना ने भारत में लघु उद्यमिता को बढ़ावा देकर न केवल रोजगार सृजन किया, बल्कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को भी नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। हालाँकि, इन योजनाओं की पूर्ण सफलता के लिए लाभार्थियों को वित्तीय शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और निरंतर समर्थन प्रदान करना अनिवार्य है।

स्टैंड अप इंडिया योजना (2016)– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को **₹**10 लाख से **₹**1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देना।

डिजिटल इंडिया मिशन (2015)– सरकार के सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाना, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल ढांचा मजबूत करना, नागरिकों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़नाम मुख्य लक्ष्य हैं। भीम ऐप (BHIM App) का आरंभ, यूपीआई (Unified Payments Interface) प्लेटफॉर्म की स्थापना, डिजिटल भुगतान का उत्सव (DigiDhan Melas) योजना की महत्वपूर्ण पहल हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ना, मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं में भारी वृद्धि योजना के प्रभाव हैं।

आधार आधारित पहचान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और भीम ऐप ने भारत के वित्तीय समावेशन अभियान को एक डिजिटल आयाम प्रदान किया। 2010–2021 के दशक में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने न केवल

बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाया बल्कि गरीब और वंचित तबकों को मुख्यधारा अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी ऐतिहासिक योगदान दिया।

हालाँकि, डिजिटल समावेशन की चुनौतियों का समाधान करते हुए साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी अवसंरचना पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है ताकि समावेशी और सतत आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 2010 से 2021 के दौरान भारत ने वित्तीय समावेशन को एक मिशन का रूप दे दिया। विभिन्न योजनाओं और डिजिटल पहलों के समन्वय से भारत ने करोड़ों वंचितों को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से जोड़ा। यद्यपि इन पहलों के समक्ष कई चुनौतियाँ भी थीं, लेकिन समग्र दृष्टि से यह अवधि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व प्रगति का कालखंड रही।

आधार आधारित वित्तीय सेवाएँ– एक विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना। KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को सरल बनाना। तत्पश्चात खाता खोलने की प्रक्रिया सरल और त्वरित हुई। वित्तीय धोखाधड़ी में कमी आई।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना– कम प्रीमियम दरों पर जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान करना, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना।

RBI और अन्य संस्थाओं की पहलें–

Business Correspondent Model: दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने हेतु बैंक मित्रों का गठन।
Payment Banks का लाइसेंस, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank आदि को अनुमति।
Financial Literacy Centres (FLCs)& ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए।
मोबाइल बैंकिंग, ई–वालेट्स, यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने छोटे व्यापारियों और आम जनता को सुलभ वित्तीय साधन प्रदान किए।
फिनटेक कंपनियों के आगमन ने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ और समाधान– भले ही भारत ने 2010– 2021 के बीच वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की हो, फिर भी कुछ गंभीर चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वित्तीय समावेशन का लाभ समाज के सबसे निचले तबकों तक पूरी तरह नहीं पहुँच सकेगा। इस भाग में हम प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधान का विश्लेषण करेंगे।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में बैंक शाखाओं, एटीएम, और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी, दूरस्थ इलाकों में पहुँच की कमी से वित्तीय सेवाएँ सीमित और महँगी होती हैं। जानकारी की कमी से गरीब और अशिक्षित वर्ग बैंकिंग, बीमा, निवेश जैसे सेवाओं का उपयोग कैसे करें, यह नहीं जानते, वित्तीय संस्थाओं के प्रति विश्वास की कमी, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्गों में। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट स्पीड और स्मार्टफोन उपयोग में कमी। तकनीकी ज्ञान की कमी व डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान का सुरक्षित उपयोग समझने में कठिनाई। कई वित्तीय उत्पाद (जैसे बीमा, पेंशन, म्यूचुअल फंड) आम जनता के लिए जटिल और कठिन समझ के होते हैं। सरल, लोकल भाषा में जानकारी और कस्टमर सपोर्ट की कमी रहती है। जो वित्तीय समावेशन की प्रमुख चुनौतियाँ है। महिलाओं का वित्तीय सहभागिता में पिछड़ना। अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अपेक्षाकृत कठिन बनी

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

रहती है। कम बैंक शाखाएँ होना, विशेष रूप से पूर्वोत्तर, हिमालयी और आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में। कम वित्तीय सेवा प्रदाता, माइक्रोफाइनेंस, NBFCs की सीमित पहुँच। डिजिटल लेन–देन में साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, डेटा चोरी के मामलों में वृद्धि। वित्तीय अनपढ़ ग्राहकों को नकली योजनाओं या निवेश घोटालों का शिकार बनाया जाता है।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकिंग संवाददाता (Banking Correspondents) मॉडल को मजबूत करना। डिजिटल बैंकिंग हब, मोबाइल वैन आधारित बैंकिंग, मिनी एटीएम्स और आधार–आधारित माइक्रो एटीएम्स का व्यापक उपयोग। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मिशन, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों में नियमित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम चलाना। स्थानीय भाषाओं में सामग्री, सरल भाषा और विजुअल मीडिया के माध्यम से वित्तीय उत्पादों की जानकारी प्रदान करना। डिजिटल साक्षरता अभियानों का विस्तार, विशेषकर महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच। यूजर–फ्रेंडली एप्लिकेशन, कम शिक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए सरल, सुरक्षित और बहुभाषीय डिजिटल भुगतान एप्लिकेशन। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल लेन–देन को सुरक्षित बनाने के लिए ग्राहकों को बुनियादी साइबर सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण देना। महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना। महिला केंद्रित बैंकिंग उत्पाद, महिलाओं के लिए विशेष बचत खाते, ऋण योजनाएँ और बीमा उत्पाद। महिला बैंकिंग प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का कार्य करना होगा। लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks) और पेमेंट बैंकों को प्रोत्साहित करना। इनोवेटिव ऋण मॉडल, बिना गारंटी वाले ऋण (Collateral&free Loans) को बढ़ावा देना।

सरकारी और निजी क्षेत्र का समन्वय, CSR फंड्स और पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन को गति देना। लचीलापन, विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लिए अनुकूलित नीतियाँ बनाना। निगरानी और मूल्यांकन, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन और सुधार। केन्या का MPESA मॉडल, मोबाइल के माध्यम से धन स्थानांतरण और भुगतान की सफलता से भारत को प्रेरणा मिली है।

बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक मॉडल, सूक्ष्म वित्तपोषण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है।

ब्राजील का एजेंट बैंकिंग मॉडल, दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुँचाने के लिए एजेंट नेटवर्क का विस्तार।

भारतीय वित्तीय समावेशन अभियान ने 2010–2021 में ऐतिहासिक प्रगति की है, लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। यदि भारत को एक पूर्णतः समावेशी, सतत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी है, तो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल पहुँच, सामाजिक समावेशन और तकनीकी नवाचारों पर निरंतर ध्यान देना होगा। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वय और जागरूकता ही वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में बदल सकता है।

वित्तीय समावेशन का सीधा संबंध भारत के सतत विकास लक्ष्यों से है। जब वित्तीय सेवाएँ समाज के हर वर्ग, विशेषकर वंचित और गरीब वर्गों तक पहुँचती हैं, तो वे अधिक समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देती हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

वित्तीय समावेशन भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। हालांकि, इसे पूर्ण रूप से साकार करने के लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, महिलाओं के लिए वित्तीय उत्पादों को सरल बनाना, और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्तीय समावेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे सही दिशा में लागू करने से भारत एक समृद्ध, सशक्त और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकता है।

वित्तीय समावेशन, जो कि आमतौर पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की प्रक्रिया है, भारत की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2010–2021 के बीच भारत में वित्तीय समावेशन ने कई सकारात्मक बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे लाखों लोग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा पाए। हालांकि, इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिनमें डिजिटल डिवाइड, भौगोलिक असमानता, और वित्तीय साक्षरता की कमी जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि जन–धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुद्रा योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड, आदि।

फिर भी, इन पहलों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम महिला सशक्तिकरण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी बैंकिंग संरचनाओं के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

भारत के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। SDG 1 (गरीबी उन्मूलन), SDG 2 (शून्य भूख), SDG 3 (स्वास्थ्य और कल्याण), SDG 5 (लिंग समानता), SDG 8 (सामाजिक और आर्थिक वृद्धि), और SDG 10 (असमानताओं को घटाना) जैसे लक्ष्य वित्तीय समावेशन के माध्यम से साकार किए जा सकते हैं। इस प्रकार, भारत की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन एक प्रभावी और आवश्यक कदम है। इसके लिए सरकारी नीतियों, निजी क्षेत्र की सहभागिता और समाज के विभिन्न वर्गों की जागरूकता में निरंतर सुधार की आवश्यकता होगी।

वित्तीय समावेशन को सही दिशा में लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम तकनीकी नवाचारों, ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाओं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष पहलुओं को प्राथमिकता दें। तभी भारत एक समृद्ध, सशक्त और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकता है।

सन्दर्भ सूची–

1- Rangarajan, C- (2008)- "Report of the Committee on Financial Inclusion-" Ministry of Finance, Government of India-
2- India Financial Inclusion Report 2019- National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)-
3- Panda] B- (2017)- "Financial Inclusion and Rural Development in India-" Indian Journal of Economics and Development, 5(10), 34-39-
4- World Bank 2020- "Financial Inclusion Data-" World Bank, www.worldbank.org-
5- Government of India (2014)- "Jan Dhan Yojana-" Ministry of Finance, Government of India-
6- Sharma, S- (2016)- "Financial Inclusion in India: Challenges and Opportunities-" The Journal of Finance and Economics, 4(3) 58-65-

7- Kochhar] R- 2020- "Digital Financial Inclusion: A New Dawn for the Indian Economy-" Indian Economic Review, 42 (2),105-121-
8- BIS (2018)- "The Role of Financial Inclusion in Achieving Sustainable Development-" Bank for International Settlements-
9- MUDRA Report 2017- "Micro Units Development and Refinance Agency Ltd (MUDRA) Scheme Impact Assessment-" Government of India-
10- Pattnaik, S- 2019- "Financial Inclusion and Economic Empowerment of Women in India-" Journal of Gender Studies, 8(2), 21-30-
11- International Monetary Fund IM, 2020- "Financial Inclusion in the Digital Age-" IMF Working Paper Series-
12. KPMG 2020- "India's Digital Banking Revolution-" KPMG Insights www.kpmg.com